

प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के जलग्रहण प्रबंधन घटक 2.0 (सी एस एस)

Demand No. 88

वित्तीय परिवव्य (करोड़ रुपए )	आउटपुट 2023-24			आउटकम 2023-24		
	आउटपुट	संकेतक	लक्ष्य 2023-24	आउटकम	संकेतक	लक्ष्य 2023-24
2200	वाटरशेड परियोजनाओं में बारानी/अवक्रमित भूमि का विकास	1.1. अवक्रमितआच्छादित भूमि / विकसित बारानी क्षेत्र(लाख हेक्टर में)	5.69	वाटरशेड परियोजना ओं की बेहतर दक्षता	2.1 जोत क्षेत्र में बदलाव (लाख हेक्टर में)(YoY)	2.16
		1.2. मिट्टी और नमी संरक्षण गतिविधियों से आच्छादित क्षेत्र(लाख हेक्टर में)	3.12		2.2 कृषकों की वार्षिक आय में बदलाव (YoY)	10.5%
		1.3. वृक्षारोपण के अंतर्गत लाया गया क्षेत्र (लाख हेक्टर में)	1.18		2.3लाभान्वित किसानों की संख्या (लाख में)	9.34
		1.4. सृजित/नवीनीकृत जलसंचयन संरचनाओं की संख्या(लाख में)	0.60		2.4 रक्षात्मक सिंचाई के अंतर्गत लाया गया क्षेत्र (लाख हेक्टर में)	1.55
		1.5. विविध फसलों के अंतर्गत आनेवाला क्षेत्र/फसल प्रणालियों में परिवर्तन(लाख हेक्टर में)	1.06		2.5 उत्पन्न रोजगार की संख्या(दिवस-मानवलाख में)	197.53
		1.6. शून्य/एकल फसल से दुगनी या अधिक फसल के लिए लाया गया क्षेत्र(लाख हेक्टर में)	1.18			

**Watershed Development Component 2.0 of Pradhan Mantri Krishi SinchayeeYojana (CSS)**

**Demand No. 88**

FINANCIAL OUTLAY (Rs in Cr)	OUTPUTS 2023-24			OUTCOMES 2023-24		
	2023-24	Output	Indicators	Targets 2023- 24	Outcome	Indicators
2200	Development of rainfed / degraded lands in watershed projects	1.1 Area of degraded land covered/rainfed area developed (in lakh ha)	5.69	2. Improved efficiency of watershed projects	2.1. Change in cropped area (in lakh ha) (YoY)	2.16
					2.2. Change in farmer income per annum (YoY)	10.5%
					2.3. No. of farmers benefitted (in lakhs)	9.34
					2.4. Area brought under protective irrigation (in lakh ha)	1.55
					2.5. Number of man- days generated (man-days in lakhs)	197.53
		1.2 Area covered with soil and moisture conservation activities (in lakh ha)	3.12			
		1.3. Area brought under plantation cover (in lakh ha)	1.18			
		1.4. No. of water harvesting structures created/renovated (in Lakh)	0.60			
		1.5. Area covered under diversified crops/ change in cropping systems (in lakh ha)	1.06			
		1.6. Area brought from nil/single crop to double or more crop (in lakh ha)	1.18			

डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) (सीएस)

वित्तीय परिव्यय (रूपए करोड़ में)	आउटपुट 2023-24			आउटकम 2023-24				
	आउटपुट	संकेतक	लक्ष्य 2023-24	आउटकम	संकेतक	लक्ष्य 2023-24		
2023-24	1. देश के सभी जिलों में भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण (पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर जहां सामुदायिक अधिकारों का मुद्दा है।)	1.1. कम्प्यूटरीकृत अधिकारों के अभिलेख (आरओआर) (गांवों की संख्या)	20,000	1. नागरिकों को जीवनयापन में आसानी	1.1. गांवों का प्रतिशत, जहां सीएससी, कियोस्क, ऑनलाइन आदि के माध्यम से अधिकारों के अभिलेखों तक पहुँच बनाई गई है।	95		
		1.2. डिजिटलीकृत मानचित्र/एफएमबी (संख्या में)	15,00,000					
		1.3 भूकर मानचित्रों/एफएमबी के साथ एकीकृत अधिकारों के अभिलेख (गांवों की संख्या)	40,000					
		1.4. गांवों की संख्या जहां भू-संदर्भित भूकर मानचित्र/एफएमबी हैं।	50,000					
	2. देश के सभी जिलों में रजिस्ट्रीकरण का कम्प्यूटरीकरण	2.1. कम्प्यूटरीकृत उप-रजिस्ट्रार कार्यालयों (एसआरओ) की संख्या	100		2. संपत्ति की रजिस्ट्री करने में आसानी	1.2 गांवों का प्रतिशत जहां डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित अधिकारों के अभिलेख जारी किए गए हैं।	70	
	3 जिलों में रजिस्ट्रीकरण के साथ भूमि अभिलेखों (आरओआर) का एकीकरण	3.1 राजस्व कार्यालयों के साथ जोड़े और एकीकृत किए गए उप-रजिस्ट्रार कार्यालयों की संख्या	150					
	4. किसानों को ऑटो क्रेडिट के लिए समर्थ किए गए जिले	4.1. बैंक के साथ भूमि अभिलेखों (आरओआर) का एकीकरण (जिलों की संख्या)	150					
	5. आधार आधारित प्रमाणीकरण के लिए तैयार गांव	5.1. आधार के साथ भूमि अभिलेखों (आरओआर) का एकीकरण (गांवों की संख्या)	50,000			50,000	2.1 राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (एनजीडीआरएस)/समकक्ष प्रणाली के माध्यम से रजिस्ट्रीकृत दस्तावेजों/विलेखों की संख्या (वर्ष-वार)	1000000

Digital India Land Records Modernization Programme (DILRMP) (CS)

FINANCIAL OUTLAY (Rs in Cr)	OUTPUTS 2023-24			OUTCOMES 2023-24			
	2023-24	Output	Indicators	Targets 2023-24	Outcome	Indicators	Target 2023-24
195.75	1. Computerization of Land Records across districts of the country(except NE States having community rights issue)	1.1. Record of Rights (RoRs) computerized (No. of villages)	20,000	1. Ease of living of citizens	1.1. Percentage of villages where RoRs are made accessible through CSC, Kiosk, Online, etc.	95	
		1.2. Maps/FMBs digitized (in nos.)	15,00,000				
		1.3. RoRs integrated with cadastral maps/ FMBs (No. of villages)	40,000				
		1.4. No. of villages having geo-referenced cadastral maps/FMBs	50,000				
	2. Computerization of Registration across districts of the country	2.1. No. of Sub- Registrar Offices (SROs) computerized	100		1.2 Percentage of villages where digitally signed RoR are issued	70	
	3. Integration of Land Records (RoRs) with registration in districts	3.1. No. of SROs connected and integrated with revenue offices	150				
	4. Districts enabled for auto credit to farmer	4.1. Integration of Land Records (RoRs) with Bank (No. of Districts)	150				
	5. Villages ready for Aadhar based authentication	5.1. Integration of Land records (RoRs) with Aadhaar (No. of Villages)	50,000		2. Ease of registering property	2.1. No. of documents/deeds registered through National Generic Document Registration System (NGDRS)/ equivalent system (Year wise)	1000000
						2.2. No. of SRO integrated with NGDRS/ equivalent system	500